उत्तर प्रदेश

ई-संदेश

18 अप्रैल, 2018 • वर्ष 1, अंक 13

सात दिन – सात पृष्ठ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने सरकारी आवास 5, कालिदास मार्ग पर इजराइल के राजदूत श्री डेनियल कार्मन से भेंट की

• बुन्देलखण्ड के विकास की नई इबारत लिखेगा डिफेन्स कॉरिडोर • दलित मित्र सम्मान से विभूषित हुए मुख्यमंत्री • ग्राम स्वराज अभियान से आएगा बदलाव • सौभाग्य योजना से निर्धन परिवारों के जीवन में उजाला • मई से शुरू होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का निर्माण • प्रदेश में अब तक 3.90 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद

संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश

डिफेन्स कॉरिडोर
बुन्देलखण्ड के विकास की नई इबारत लिखेगा

उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश में विकास के पायदान पर सबसे कमजोर क्षेत्र बुन्देलखण्ड और पूर्वान्चल रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इन क्षेत्रों के समुचित विकास हेतु कटिबद्ध हैं और उनके अथक प्रयासों से सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की नई राह खुल गयी है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा बुन्देलखण्ड क्षेत्र में डिफेंस कॉरिडोर की घोषणा के बाद से ही लगातार रक्षा मंत्रालय व प्रदेश सरकार के अधिकारी कई बैठकें कर चुके हैं, जिसके सुखद परिणाम आये हैं। राज्य सरकार डिफेंस कॉरीडोर की स्थापना हेतु पूरे उत्साह के साथ काम कर रही हं। डिफेंस कॉरिडोर के लिए यहां पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं। उद्यमियों के लिए सम्पर्क मार्ग की सुविधा है। यह कॉरिडोर इस क्षेत्र के ऑद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा।

डिफेंस कॉरिडोर की मॉनीटरिंग प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण यहां के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में एक्स आर्मी पर्सन अधिक है, उनका लाभ लिया जायेगा। डिफेंस सेक्टर में उद्योग जगत के प्रतिभाग करने पर सरकार उनकी हर सम्भव मदद करेगी।

“ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के 'मेक इन इण्डिया' में बुन्देलखण्ड क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश के विकास और रोजगार सृजन में डिफेंस कॉरिडोर का अहम स्थान है। झांसी में सबसे अच्छी कनेक्टिविटी है, जिसके कारण डिफेंस कॉरिडोर यहां के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कॉरिडोर बन जाने के बाद बुन्देलखण्ड का पिछड़ापन और आर्थिक गरीबी दूर होगी। क्षेत्र के प्रतिभाशाली युवाओं को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए कॉरिडोर एक ऐसा माध्यम बनेगा, जिसके द्वारा क्षेत्र का तेजी से विकास होगा।

उत्तर प्रदेश में युवाओं की संख्या अधिक है, जिन्हें आगे लाया जा रहा है, ताकि उनके इनोवेशन का लाभ लिया जा सके। युवाओं को कॉरिडोर के सम्बन्ध में जानकारी दी जाएगी ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।

सात जिले होंगे शामिल

प्रस्तावित कॉरिडोर में 7 जिले शामिल हैं। कॉरिडोर कें निर्माण हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध है और पर्याप्त टेस्टिंग रेंज भी है। लगभग 3 हजार हेक्टेयर से ज्यादा भूमि चिन्हित कर ली गयी है। आगरा–लखनऊ एक्सप्रेस–वे व बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस–वे से आवागमन की सुविधा मिलेगी। सरकार प्रदेश की ऑर्डिनेसं फैक्ट्रियों के विस्तार पर भी ध्यान दे रही है।

झांसी डिफेंस कॉरिडोर में एयरक्रॉफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री व ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग इण्डस्ट्री विकसित की जाएंगी। भूमि के लिए जल्द ही नोटीफिकेशन किया जा रहा है। आई. आई.टी. कानपुर डिफेंस कॉरिडोर में तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराएगा। स्किल इन्फ्रास्ट्रक्चर को भी डिफेंस कॉरिडोर से लिंक किया जाएगा। इसका सीधा लाभ क्षेत्र को मिलेगा।

डिफेंस कॉरिडोर के साथ ही फूड प्रोसेसिंग पार्क और स्किल डेवलपमेंट को जोड़कर क्षेत्र के विकास को गति दी जायेगी। सभी को जोड़कर समन्वित ढंग टाइम लाइन में कार्य पूरा होगा। इससे यहां की कैपिटल इनकम में यह क्षेत्र अग्रणी होगा। यहीं रोजगार मिलने से युवाओं में पलायन की समस्या समाप्त होगी।

ग्राम स्वराज अभियान से आएगा बड़ा बदलाव

भारतीय संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉ. बी.आर. आंबेडकर की जयन्ती के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में गरीबों, वंचितों, दलितों और समाज के अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान के कार्यक्रम **'ग्राम स्वराज अभियान'** का संचालन किया गया। इस अभियान के तहत सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में बदलाव की कई योजनाएं संचालित की गईं।

अनुसूचित जाति तथा जनजाति बाहुल्य गावों को मिलेगा लाभ

'ग्राम स्वराज अभियान' के तहत सभी जनपदों के प्रत्येक विकास खण्ड के सर्वाधिक अनुसूचित जाति एवं जनजाति वाले गांवों को केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संतृप्त किया जायेगा।

इसके साथ ही, प्रत्येक नगर निगम, नगर पालिका परिषद तथा नगर पंचायत के अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य आबादी वाले वार्डों को भी केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से संतृप्त किया जाएगा।

इस अभियान के तहत ऊर्जा विभाग द्वारा सौभाग्य योजना में प्रदेश के चयनित अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य 3387 ग्रामों के सभी अविद्युतीकृत घरों में जाकर विद्युत कनेक्शन देने का कार्य संचालित किया जा रहा है।

समाज के अन्तिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का लक्ष्य

सामाजिक एवं आर्थिक विषमता को दूर करने और साधनों के समान वितरण के लिए अनेक योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके तहत स्वास्थ्य के लिए **'आयुष्मान भारत'**, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए **'जन–धन' योजना** लागू की गई है। केन्द्र की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी संसाधनों के बिना भेदभाव के वितरण के लिए हर सम्भव कदम उठाए हैं।

विभिन्न चारणें में मिलेगा शासन की योजनाओं का लाभ

शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए और लाभार्थियों को लाभ पुहंचाने के लिए 'ग्राम स्वराज अभियान' के तहत विभिन्न चरणों में शासन की योजनाएं गरीबों, वंचितों, दलितों तक पहुंचाई जाएंगी, जिनमें सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जीवन रक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्डअप योजना, स्टार्टअप योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना शामिल हैं।

18 अप्रैल को 'स्वच्छ भारत दिवस', 20 अप्रैल को उज्ज्वला योजना, 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 28 अप्रैल को ग्राम स्वराज दिवस, 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस, 02 मई को किसान कल्याण दिवस तथा 05 मई को युवा आजीविका दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ■

सुचारू विद्युत आपूर्ति के लिए नये उपकेन्द्रों की सौगात

प्रदेश को मिले 15 नवनिर्मित विद्युत उपकेन्द्र

इस अवसर पर मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को पारेषण निगम के 15 नवनिर्मित उपकेन्द्रों की सौगात दी। इनमें जनपद सहारनपुर, आजमगढ़ तथा फर्रुखाबाद के 220 के0वी0 क्षमता के 1–1 तथा जनपद लखनऊ में 220 के0वी0 क्षमता के 02 उपकेन्द्र शामिल हैं। जनपद शामली, सहारनपुर, कन्नौज, देवरिया, अमेठी, गोरखपुर, बिजनौर, आगरा, बदायूं तथा बाराबंकी में 132 के0वी0 क्षमता के 1–1 उपकेन्द्र भी प्रदेश की जनता को समर्पित किए। यह उपकेन्द्र स्थानीय जनता को सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने में उपयोगी भूमिका का निर्वहन करेंगे।

सौभाग्य योजना से निर्धन परिवारों के जीवन में उजाला

गरीब, दलित, विद्युत कनेक्शन से वंचित लोगों को मिल रहा है नि:शुल्क विद्युत कनेक्शन

किसानों के लिए विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित तथा डार्क जोन में उपलब्ध कराए गए ट्यूबवेल कनेक्शन

योजनाओं में बिचौलियों को हटाकर सीधे भुगतान की राशि लाभार्थी के खाते में

बिजली आपूर्ति में भेदभाव वाली व्यवस्था समाप्त की गई

पिछले वर्ष 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जयन्ती पर राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी जनपदों में बिना भेदभाव के समान रूप से बिजली आपूर्ति का निर्णय लेते हुए, बाबा साहब के विचारों और आदर्शों में अपनी आस्था प्रकट की थी। तभी से प्रदेश के सभी जनपद मुख्यालयों को 24 घण्टे, तहसील मुख्यालयों तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र को 20 घण्टे तथा ग्रामीण इलाकों में 18 घण्टे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। भेदभाव वाली व्यवस्था को समाप्त कर वर्तमान राज्य सरकार ने बाबा साहब डॉ. आंबेडकर को अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है।

जब से वर्तमान सरकार ने प्रदेश का कार्यभार सम्भाला है, ऊर्जा को विकास का आधार मानते हुए बिजली उपलब्धता की दिशा में ठोस निर्णय लिए गए हैं। इसके तहत प्रदेश के हर घर को बिजली से जोड़ा जा रहा है। वर्ष 2017–18 में 61 हजार से अधिक मजरों का विद्युतीकरण किया गया तथा लगभग 36 लाख नि:शुल्क बिजली कनेक्शन प्रदान किए गए।

प्रदेश में गरीब पविारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन देने हेतु 'सौभाग्य' (प्रधानमंत्री सहज हर घर बिजली योजना) की शुरूआत की गई थी। इस योजना के तहत गरीब ग्रामीण परिवारों को नि:शुल्क बिजली कनेक्शन तथा अन्य को 50 रुपए की मासिक किश्त पर संयोजन दिया जा रहा है। शहरी क्षेत्र के गरीब परिवारों को भी नि:शुल्क विद्युत संयोजन प्रदान किए जा रहे हैं। मार्च, 2018 तक पूरे प्रदेश में 40 हजार 457 विशेष शिविर लगाकर 15 लाख 88 हजार विद्युत संयोजन निर्गत किए गए। इनमें से 08 लाख 77 हजार 913 बिजली कनेक्शन गरीब परिवारों को प्रदान किए गए। इसी क्रम में, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बाहुल्य 3387 गांवों के गरीब परिवारों को मुफ्त विद्युत कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं।

मौके पर ही नया कनेक्शन देगा ई–संयोजन

सौभाग्य योजना के तहत मौके पर नया कनेक्शन देने के लिए ई–संयोजन मोबाइल एप लॉन्च किया गया है। पहली बार उपभोक्ताओं को घर बैठकर स्वयं विद्युत बिल सृजित करने तथा इण्टरनेट के जरिये उसका भुगतान करने की सुविधा भी प्रदान की गई। वर्ष 2018–19 में शहरी और ग्रामीण इलाकों में कुल 80 लाख बिजली कनेक्शन निर्गत किए जाएंगे और 62 हजार मजरों का विद्युतीकरण किया जाएगा।

मार्च 2019 तक प्रत्येक गांव को बिजली

इसके अलावा, 125 लाख एल0ई0डी0 बल्ब के वितरण, 15 हजार वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के साथ–साथ 50 हजार नवीन वितरण ट्रांसफार्मर भी वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, 33/11 के0वी0 क्षमता के 300 नवीन विद्युत उपकेन्द्रों को ऊर्जीकृत करने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि बिना किसी भेदभाव के सभी 75 जनपदों के हर क्षेत्र में बिजली पहुंचे। केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर विद्युत के क्षेत्र में तमाम उपलब्धियां हासिल कर रही हैं। 25 लाख ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई। साथ ही, ग्रिड की क्षमता बढ़ाई गई। मार्च, 2019 तक प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचे जायेगी। गरीबों का कल्याण व उत्थान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। ■

दलित मित्र सम्मान से विभूषित हुए मुख्यमंत्री

बाबा साहब का जीवन हम सभी के लिए प्रेरक : मुख्यमंत्री

शासन की सुविधाओं से वंचित व्यक्तियों को वास्तविक लाभ प्रदान करने के लिए गठित होगा कमीशन

राज्य सरकार द्वारा बाबा साहब के चित्र को सभी सरकारी कार्यालयों में लगाने के निर्देश

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। इस लोकतंत्र की नींव अर्थात् देश का संविधान बाबा साहब डॉ. बी.आर. आंबेडकर की देन है। बाबा साहब ने भारतीयों के मन में यह आत्मविश्वास जगाया कि किसी भी हालत में संघर्ष और शिक्षा के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है। संविधान केवल पूजा के लिए नहीं है, बल्कि इसे व्यवहार में भी लाया जाना आवश्यक है। आज आवश्यकता है कि हम बाबा साहब के जीवन दर्शन को अपनाकर एक श्रेष्ठ भारत का निर्माण करें, क्योंकि देश को कहां ले जाना है, इसका कर्तव्यबोध हमें होना चाहिए। यह उद्गार राज्यपाल श्री राम नाईक जी राज्यपाल जी ने डॉ. आंबेडकर की 127वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किये।

इस अवसर पर अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि डॉ0 आंबेडकर को उचित सम्मान दिलाने में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का महत्वपूर्ण योगदान है। जहां एक ओर प्रधानमंत्री जी बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर से जुड़े स्थलों को विकसित कर उनके दर्शन से वर्तमान एवं भावी पीढ़ी को जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर डॉ0 आंबेडकर की सोच के अनुरूप विकास कार्यों को भी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आजादी के बाद भी जिन गांवों को राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं था और उन्हें वोट देने का भी अधिकार नहीं था, उन्हें हमारी सरकार ने यह अधिकार प्रदान करने का काम किया।

इस अवसर पर बाबा साहब डॉ. बी.आर. आंबेडकर महासभा की ओर से मुख्यमंत्री जी को दलित मित्र सम्मान से विभूषित किया गया।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की स्कालरशिप तथा धनराशि बढ़ाई जाएगी

वर्तमान सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शत–प्रतिशत कुल 21 लाख विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप उपलब्ध करायी है। इस वर्ष 23 लाख छात्र–छात्राओं को स्कॉलरशिप दी जाएगी। साथ ही, अब यह व्यवस्था की गई है कि स्कॉलरशिप की पहली किश्त 02 अक्टूबर को तथा दूसरी किश्त 26 जनवरी को उपलब्ध करा दी जाए। स्कॉलरशिप की पात्रता हेतु आय सीमा को 02 लाख रुपये से बढ़ाकर ढाई लाख रुपये किया जाएगा। इससे अनुसूचित जाति के 50 हजार और अनुसूचित जनजाति के 500 अतिरिक्त विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त होगा।

देश डॉ0 आंबेडकर की प्रेरणा से प्रकाश पाकर निरंतर आगे बढ़ रहा है। केन्द्र सरकार ने जनधन योजना, गरीब के लिए आवास की व्यवस्था, घर में शौचालय निर्माण, नि:शुल्क बिजली कनेक्शन के माध्यम से गरीब, दलित और वंचित वर्ग के लिए बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराया है। यह न्याय और समता की स्थापना के भाषणों से नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व की केन्द्र सरकार की कर्मठता और सतत प्रयास से सम्भव हुआ है। केन्द्र सरकार के अनुरूप कार्य करते हुए प्रदेश सरकार ने भी राज्य के गरीब, दलित और शोषित वर्ग को 8.85 लाख आवास, 40 लाख शौचालय, 1.42 लाख विद्युत कनेक्शन तथा 37 लाख राशन कार्ड उपलब्ध कराकर समाज की मुख्यधारा में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की है।

केन्द्र सरकार डॉ0 आंबेडकर से जुड़े 05 स्थलों को 'पंच–तीर्थ' के रूप में विकसित कर रही है। इनमें मध्य प्रदेश स्थित उनका जन्म स्थान महू छावनी तथा लंदन का वह घर, जहां ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने अपनी पढ़ाई की, सम्मिलित हैं। साथ ही, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली स्थित महापरिनिर्वाण स्थल तथा मुम्बई में चैत्य–भूमि का भी विकास किया जा रहा है। इसके अलावा गत वर्ष दिसम्बर में प्रधानमंत्री जी द्वारा नई दिल्ली में डॉ0 बी0आर0 आंबेडकर अंतराष्ट्रीय केन्द्र राष्ट्र को समर्पित किया गया। निश्चित रूप से 'पंच–तीर्थ' स्थलों के विकास से अधिक से अधिक लोगों और विशेष तौर पर युवाओं को बाबा साहब डॉ0 आंबेडकर की दृष्टि एवं विचारों को जानने एवं समझने का अवसर मिलेगा।

गरीबों, दलितों और पिछड़ों की भलाई के लिए तत्पर है सरकार

गरीबों, दलितों व वंचितों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना योगी सरकार की प्राथमिकता है। अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों के समुचित विकास हेतु सरकार द्वारा कई योजनायें संचालित की जा रही हैं और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है योजना के वास्तविक लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हो।

दशमोत्तर छात्रवृत्ति को तोहफा

इस वर्ष दशमोत्तर छात्रवृत्ति में अनुसूचित जाति के लगभग 50 हजार विद्यार्थियों व अनुसूचित जनजाति के 500 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।

चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि, प्रबन्धन, स्नातक व परास्नातक डे–स्कॉलरों को 550 रुपए और जो विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं, उन्हें 1200 रुपए मिलेंगे। एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम., एल.एल.बी., पैरामेडिकल, एम. फार्मा के डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु डे–स्कॉलर को 530 रुपए व हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी को 820 रुपए दिए जाएंगे।

अनुसूचित जाति/जनजाति के स्नातक डिग्री हेतु बी.ए., बी.एस.सी., बी.कॉम के डे–स्कॉलर को 300 रुपए तथा हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थी को 570 रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा, जिनकी योग्यता कम से कम हाईस्कूल तक हो, उन डे–स्कॉलर्स को 230 रुपए व हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों को 380 रुपए दिए जाएंगे। अनुसूचित जाति के 50 हजार व अनुसूचित जनजाति के 500 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

निर्धन कन्याओं के विवाह हेतु 35 हजार की आर्थिक मदद

प्रदेश में गरीब परिवारों की बालिकाओं के विवाह हेतु मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना लागू की गई है। इस योजना से अनुसूचित जाति की 07 हजार बालिकाओं व अनुसूचित जनजाति की 200 बालिकाओं को लाभ मिला है। इस योजना के तहत राज्य सरकार प्रति लाभार्थी को 35 हजार रुपए उपलब्ध कराने का काम कर रही है। इस हेतु इस वित्तीय वर्ष में 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

समय पर न्याय दिलाने हेतु प्रयास

अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों को उचित व समय पर न्याय मिले, यह सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में जो मामले दर्ज होते हैं, उनका त्वरित निस्तारण हो व दोषियों को सजा मिले। लेकिन कोर्ट की संख्या कम होने के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पाता था, इसलिए 25 नये कोर्ट गठित किए जाएंगे। ■

वर्तमान सरकार ने कार्यभार ग्रहण करते ही अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के 21 लाख लोगों को स्कॉलरशिप देने का काम किया।

प्रदेश में जैव ऊर्जा उद्यमों के लिए निवेश की अपार संभावनायें

राज्य सरकार ने प्रदेश में जैव ऊर्जा प्रोत्साहन कार्यक्रम को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम के तहत उद्यमियों तथा निवेशकों को विशेष सुविधाएं सुलभ कराने की प्रयास की गई है। इसके लिए आकर्षक एवं व्यवहारिक नियमावली प्रख्यापित की गई है। इस कदम से राज्य में जैव ऊर्जा परियोजनाएं बड़ी संख्या में स्थापित होंगी और रोजगार के अधिकाधिक अवसर मिलेंगे।

विभिन्न जैव ऊर्जा परियोजनाओं जैसे–डीजल, बायो एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो गैस, बायो सीएनजी, प्रोडयूसर गैस, बायो कोल उत्पादन इकाईयों पर विशेष प्रोत्साहन देने का प्राविधान किया गया है। जैव ऊर्जा के उत्पादन से पर्यावरण संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है।

प्रख्यापित नियमावली में जैव ऊर्जा उद्यम प्रोत्साहन योजना में निवेश पर पूँजीगत अनुदान की तीन सीमायें तय की गई है। इसमें स्तर–1 की परियोजना हेतु 10 करोड़ रुपये से कम, स्तर–2 की परियोजनाओं के लिए 10 से 100 करोड़ रुपये तक तथा स्तर–3 की परियोजनओं के लिए 100 करोड़ रुपये से ऊपर की परियोजनायें ली जायेगी।

प्रदेश में बन रहा है बेहतर शिक्षा का वातावरण

उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश में शिक्षा का वातावरण बनाते हुए इससे अभिभावकों को जोड़ने के प्रसाय कर रही है, ताकि स्कूलों में बच्चों का शत–प्रतिशत दाखिला सुनिश्चित किया जा सके। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनपद चित्रकूट दौरे में ग्राम पंचायत कसहाई में 'स्कूल चलो अभियान' के तहत रैली को रवाना किया। उन्होंने नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को अपने समक्ष गृह प्रवेश भी करवाया।

मुख्यमंत्री जी ने 'स्कूल चलो अभियान' से जुड़े अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अभियान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश सरकार विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को शीघ्र दूर करने हेतु प्रयासरत है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को जूता–मोजा, स्वेटर, किताब, यूनीफार्म इत्यादि का वितरण जनप्रतिनिधियों के सहयोग से समय से कराना सुनिश्चित कराएं।

सबका साथ सबका विकास

के मूलमंत्र पर काम कर रही है सरकार

राज्य सरकार 'सबका साथ–सबका विकास' के मूलमंत्र पर काम कर रही है, ताकि समाज के सभी लोगों/वर्गों का विकास हो सके। प्रदेश सरकार पात्रता के आधार पर गरीबों और वंचितों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कर रही है।

मुख्यमंत्री जी ने यह विचार जनपद जालौन में लोक कल्याण मेले को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। इस अवसर पर उन्होंने जनपद की 126 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास तथा 149 का परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए ऐसी योजनाएं बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र का विकास हो और रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो सकें। इसीलिए प्रदेश सरकार ने आगरा–चित्रकूट वाया उरई एक्सप्रेस–वे के निर्माण का निर्णय लिया है। कालपी में पर्यटन की अपार सम्भावनाएं मौजूद हैं। इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कालपी के कागज उद्योग को 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' योजना के तहत बढ़ावा दिया जाएगा तथा इसकी विशिष्ट पहचान को भी स्थापित किया जाएगा।

17 अप्रैल 2018 को सम्पन्न प्रदेश कैबिनेट की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

मई से शुरू होगा पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का निर्माण

आगामी मई माह से आठ पैकेज में पूर्वांचल एक्सप्रेस–वे का निर्माण कार्य प्रारंभ हो जायेगा। नयी योजना के अनुसार इस परियोजना की लागत में 1559.97 करोड़ रूपये की कमी आई है और इस एक्सप्रेस–वे को 30 माह के रिकॉर्ड समय में पूरा कर लिया जायेगा।

सरकार ने एक्सप्रेस–वे से गोरखपुर और इलाहाबाद को जोड़ने का भी निर्णय लिया है। इस प्रोजेक्ट के लिए 413 गांवों में अधिग्रहण की जाने वाली जमीनों में से 90.9 प्रतिशत का अधिग्रहण हो चुका है। जमीन 120 मीटर चौड़ाई में ली गई है। जमीन की कीमत, सेंटेज, जीएसटी तथा सूटिलिटी शिफ्टिंग आदि को मिलाकर इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 23349.37 करोड़ रूपये होगी।

डीएम और कमिश्नर करेंगे प्राईवेट गोदामों के किराये का निर्धारण

जिला उद्यान अधिकारी के 50 प्रतिशत पद भरे जाएंगे सीधी भर्ती से

60 करोड़ सीसीएल मिलेगा मोहिउद्दीनपुर चीनी मिल को

गोरखपुर मेडिकल रिसर्च सेंटर के लिए 3448 वर्ग मीटर जमीन

पॉलीटेक्निक में लागू होंगी एआईसीटीई की सिफारिशें, निर्धारित होंगे वेतन

अमेठी में ध्वस्त होंगे चिकित्सा विभाग के रिहायशी और गैर रिहायशी भवन

10 लाख तक के कार्यों के लिए जरूरी नहीं होगी ई–टेडरिंग

कैबिनेट ने प्रदेश में 10 लाख रूपये तक के कार्यो के लिए ई–टेण्डरिंग की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। सभी विभागों में निर्माण कार्यो, सेवाओं, जॉब वर्क, सामग्री खरीद, चालू और दर अनुबंध के लिए प्रदेश में ई–टेंडरिंग की व्यवस्था लागू है।

जनपद मथुरा के पांच क्षेत्र पवित्र तीर्थ स्थल घोषित

राज्य सरकार ने प्रदेश के जनपद मथुरा की नगर पंचायत गोवर्धन, राधाकुण्ड, नन्दगांव, गोकुल एवं बल्देव के अधिकतम क्षेत्र को पवित्र तीर्थ स्थल घोषित किया गया है। इन तीर्थ स्थलों की पौराणिक महत्ता है। इसके साथ ही ये तीर्थ स्थल पर्यटन की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं।

प्रदेश में अब तक 3.90 लाख मीट्रिक टन गेहूँ खरीद

मूल्य समर्थन योजना के अन्तर्गत प्रदेश में खोले गए गेहूँ क्रय केन्द्रों के माध्यम से अब तक 3,90,852.47 मीट्रिक टन गेहूँ किसानों से सीधे क्रय किया गया। गत वर्ष इस अवधि में 1,32,049.92 मीट्रिक टन गेहूँ की खरीद की गयी थी। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष लगभग तीन गुना अधिक खरीद हुई है। इस योजना से अब तक 62047 किसान लाभान्वित हुए हैं तथा किसानों को देय 678.129 करोड़ रूपये के सापेक्ष शत प्रतिशत भुगतान उनके खातों में सीधे किया गया है।

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश के लिए, निदेशक डॉ. उज्ज्वल कुमार द्वारा प्रकाशित. सम्पादक : सुहेल वहीद अंसारी